आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology in modern India)

भारत में आज जिन सिद्धान्तों के आधार पर समाजशास्त्र का तेजी से विकास हो रहा है, उसका इतिहास अधिक पुराना नहीं है। यूरोप में यद्यपि 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध (later half) में ही आधुनिक समाजशास्त्र की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से अमरीका, इंगलैंड, जर्मनी और फ्रांस ने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा जितनी तेजी से प्रगति की, वह भारत के लिए भी एक आकर्षण की बात थी। भारत में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक कोई ऐसा विज्ञान विकसित नहीं हो सका था जो सम्पूर्ण समाज का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर सकता हो। इस समय तक सभी अध्ययन केवल आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अथवा दार्शनिक आधार पर किये जाते थे। पश्चिम में समाजशास्त्र का विकास होने के साथ ही अनेक भारतीय विद्वानों का ध्यान भी समाजशास्त्र की ओर आकर्षित होना आरम्भ हुआ। इसके फलस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले तक भारत में सम्पूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययन मुख्यतः इंगलैण्ड में प्रतिपादित सैद्धान्तिक विचारधारा से ही प्रभावित रहे, जबकि स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन, अमरीका की समाजशास्त्रीय परम्परा से प्रभावित होने लगा।

आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का इतिहास

(History of Sociology in modern India.)

भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले मुम्बई (बम्बई) विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1916 में आरम्भ किया गया। सन् 1919 में यहाँ समाजशास्त्र के पृथक् विभाग की स्थापना करके पैट्रिक गिड्स (Patric Geddes) को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके दो वर्ष पश्चात ही लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय को मान्यता दी। सन् 1928 में मैसूर विश्वविद्यालय में इस विषय को डिग्री स्तर पर मान्यता दी गयी जबकि पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग सन् 1939 में स्थापित हुआ। इन सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की स्थापना एक पृथक् विषय के रूप में न होकर इसे अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र अथवा सामाजिक दर्शन के रूप में जोड़ रखा गया था। यही कारण है कि आरम्भ में भारत में जो विद्वान समाजशास्त्रीय विचारधारा को लेकर आगे बढ़े और जिन्होंने इस विषय को समृद्ध बनाने के व्यापक प्रयत्न किये, वे मूलरूप से अर्थशास्त्री तथा मानवशास्त्री ही थे। इसके पश्चात भी वास्तविकता यह है कि स्वतन्त्रता के पूर्व तक भारत में समाजशास्त्र का न तो अधिक विस्तार हो सका और न ही इसके पृथक् महत्व को स्वीकार किया जा सका। सन् 1947 के बाद से समाजशास्त्र की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि

इस समय से समाज का नये सिरे से पुनर्गठन करना भी आवश्यक समझा जाने लगा। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अतिरिक्त आगरा, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, कुमायूँ, गढ़वाल, रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड और अवध विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक पृथक और महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, विक्रम, जीवाजी, इन्दौर, सागर, जयप्रकाश प्रताप सिंह, बिलासपुर और रायपुर विश्वविद्यालयों तथा राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर तथा जयपुर आदि विश्वविद्यालयों तथा राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर तथा जयपुर आदि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभागों की स्थापना हुई। बिहार में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बोधगया, भागलपुर तथा झारखण्ड में राँची समाजशास्त्र के प्रमुख अध्ययन केन्द्र बन गये। इसके अतिरिक्त दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, नागपुर, उस्मानिया, बड़ौदा, पूना, मद्रास, पंजाब, उत्कल, रोहतक, कुरुक्षेत्र तथा अनेक दूसरे विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र विषय को तेजी से लोकप्रियता मिलने लगी।

भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए अनेक शोध संस्थाओं की भी स्थापना की गयी है। इनमें टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस, बम्बई; जे. के. इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एण्ड सोशल वर्क्स, लखनऊ तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ आगरा आदि प्रमुख हैं। इन सभी संस्थाओं के प्रयत्नों से भविष्य में समाजशास्त्र का विकास और अधिक तेजी से होने की आशा की जा सकती है।